Q5 Discuss the merits and demerits of direct taxes and indirect taxes. (प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर.)

or

Define taxes. Distinguish between direct taxes and indirect taxes.

कर सार्वजनिक आय का प्रमुख स्रोत है। इसका वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। इनमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर महत्वपूर्ण है। इन करों की परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रीयों भिन्न-भिन्न रूपों में किया है।

According to J. S. Mill के अनुसार "a direct tax is one demanded from the very person who it is intended or desired should pay it and indirect tax is one demanded from one person in the expectation and intention that he shall indemnify himself at the expenses of another.

According to Dalton "a direct tax is really paid by the person on whom it is legally imposed while indirect tax is imposed on one person but paid partly wholly by another, owing to the consequential change in the terms of some contract or bargain between them.

ऊपर दिए गए परिभाषाओं से स्पष्ट है की जब किसी कर का करापात (impact) or

करापात (Incidence) तब वह प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसके विपरीत जब कर का दबाव और भार भिन्न-भिन्न लोगों पर पड़ता है तो उसे परोक्ष कर कहा जाता है।

merits of Direct taxes.

प्रत्यक्ष करों के कई लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं।

1) Equity (समता) — प्रत्यक्ष कर प्रणाली समता मूलक होता है क्योंकि यह करदाता की योग्यता पर निर्भर करता है। इसमें अधिक आय वाले लोगों को अधिक कर और कम आय वाले लोगों को कम कर देना पड़ता है।

2) Certainty (निश्चितता) — प्रत्यक्ष कर प्रणाली में निश्चितता का गुण पाया जाता है, क्योंकि करदाता को यह मालूम रहता है की उसे कब और कितना भुगतान करना है। सरकार को भी यह मालूम होता है की उसे किसना राजस्व की प्राप्ति होगी।

3) Elasticity (लोच) — यह कर प्रणाली में लोच का गुण पाया जाती है। आय में परिवर्तन होने से कर की मात्रा में स्वतः परिवर्तन हो जाता है।

4) प्रगतिशीलता (Progressive) — यह कर प्रणाली ऊँचे आय वालों पर बढ़ी हुई दर से कर लगाया जाता है और आय में कमी होने की वजह से घट जाता है।

5) जागरूकता (Consciousness) — यह कर प्रणाली के अंतर्गत कर दाता भुगतान स्वयं करता है इसलिए राजकीय कार्यक्रम और व्यय के प्रति जागरूक रहता है।

Demerits of direct taxes.

जहाँ प्रत्यक्ष कर के कई गुण हैं उसके कई दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं।

1) Tax evasion (करों की चोरी) — प्रायः प्रत्यक्ष कर देने वाले व्यक्ति इसके प्रगतिशील दरों से बचने के लिए आय एवं व्यय का सम्पूर्ण विवरण नहीं करते। इसलिए कर में अपवंचन की सम्भावना बनी रहती है।

2) Arbitrary rates — प्रत्यक्ष करों की दरें में भी निश्चित करने का कोई ठोस आधार नहीं है क्योंकि यह करदान योग्यता की धारणा पर आधारित है जिसका सही अनुमान लगाना कठिन है।

3) असुविधा जनक — यह कर प्रणाली असुविधाजनक होती है क्योंकि इसका भुगतान एक साथ करना पड़ता है और सरकार को अनेक बार कार्यालयों में जा और वकीलों से परामर्श लेना होता है इससे लोगों को असुविधा होती है।

4) अमितव्ययी — इन करों को वसूलने में काफी धन खर्च करना पड़ता है क्योंकि कर का दर बढ़ने से कर दाता में असंतोष फैलता है। सरकार को कर वसूलने में अधिक खर्च करना पड़ता है।

Merits of indirect taxes

प्रत्यक्ष कर के कई गुण हैं जो निम्नलिखित हैं:-

1) convinient — (सुविधाजनक) — परोक्ष कर प्रायः वस्तुओं के मूल्य में शामिल रहते हैं अतः न तो कर भार वहन करने वाले लोगों को इसका हिसाब रखना पड़ता है और न तो ~~ऋ~~ इन्हें अधिक मात्रा में एक ही बार चुकाना पड़ता है इसलिए कर दाता को वास्तविक भार का अनुभव नहीं होता।

2) Tax evasion impossible — कर वंचन सम्भव नहीं यह कर प्रणाली में कर दाताओं को चोरी करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह कर पहले उत्पादकों या व्यापारियों से वसूल किए जाते हैं। बाद में वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करके उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है।

3) सुविधाजनक — यह कर प्रणाली का गुण है की ये सुविधाजनक होते हैं।

4) Elasticity — इस कर प्रणाली में लोच का गुण पाया जाता है अर्थात् करों की दर में वृद्धि करके सरकार अपनी आय बढ़ा लेती है।

5) Popular लोकप्रीय — यह कार प्रणाली लोकप्रीय होती है।

Demerits of indirect taxes.

1) न्याय में कमी Lack of justice. — यह कर प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है की अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से लगाए जाते हैं।

2) Uncertain — यह कर प्रणाली अनिश्चित होती है क्योंकि सरकार को यह पता नहीं होता की सरकार को कितनी आय प्राप्त होगी और नहीं तो उपभोगता को भी इसकी जानकारी होती है।

3) करवंचन (tax evasion) — इस कर प्रणाली में उपभोक्ता करों से नहीं बच पाते लेकिन विक्रेता अपने हिसाब से कर देते हैं बेची हुई राशि कम दिखाते हैं और करों की चोरी में सफल हो जाते हैं।

4) उपभोग और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव — परोक्ष कर प्रणाली का बड़ा दोष यह है की करों के कारण मूल्य बढ़ जाती है जिससे उनका उपभोग कम हो जाता है और उत्पादन की मात्रा भी कम हो जाती है।

इस प्रकार ऊपर दिए गए बातों से स्पष्ट है की प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों ही कर प्रणालियों के अलग-अलग गुण दोष हैं। अतः वास्तव में किसी भी देश में दोनों प्रकार के करों के बीच एक उचित संतुलन होना चाहिए। दोनों कर एक दूसरे के दोष को दूर करते हैं। इस सम्बन्ध में बड़ा ही सुन्दर कथन Great

Scotman का कथन है की " I can never think of Direct and indirect taxation except as I should think of two attractive sisters who have been introduced into the gay world of London, each with an ample fortune, both having the same parentage, for the parents of I believe to be necessity and invention, differing only as sisters may differ."

(Factors responsible for increase in public expenditure (सार्वजनिक व्यय)

Q6 हाल के वर्षों में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। क्या यह वृद्धि वांछनीय है?

उत्तर → सार्वजनिक व्यय का राजस्व अर्थशास्त्र में उतना ही महत्व है जितना महत्व अर्थशास्त्र में उपभोग का है। सार्वजनिक वित्त की ज्यादातर क्रियाएं इसी के चारों ओर घूमती हैं। वैसे तो प्राचीन अर्थशास्त्रीयों ने प्राचीन अर्थशास्त्रीयों ने सार्वजनिक व्यय की अवहेलना की परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के बाद राज्य की आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने लगी और सार्वजनिक व्यय में भी लगातार वृद्धि होने लगी। Dalton के शब्दों में कहा जा सकता है कि "Modern development more over in the fields have made it necessary for public authorities to assume new functions which could not infact have been assumed by the private enterprerise at all".

इस प्रकार विगत वर्षों से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए जो निम्नलिखित हैं।

① कल्याणकारी राज्य की स्थापना (welfare state) — आधुनिक समय में राज्य ने कल्याणकारी धारना को स्वीकार किया है। आज सरकार को शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, बेरोजगारी, गरीबी दूर करना, वृद्धावस्था पेनसन का शिशु कल्याण एवं अन्य

सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं चला रही है फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है।

② प्रशासनिक व्यय में वृद्धि – विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातंत्रीय व्यवस्था (Democracy) को अपनाया है जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को M.P, M.L.A तथा स्थानीय निकायों के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक मशीनरी पर बहुत खर्च होता है।

③ प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि (Defence) – वर्तमान समय में युद्ध लड़ने तथा उसके लिए तैयारी करने के लिए भारी मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। कुल व्यय का प्रतिरक्षा पर सबसे अधिक व्यय करना पड़ता है। इसमें न केवल सैनिक और सैन्य सामग्री पर व्यय होता है बल्कि युद्ध के लिए ऋणों पर ब्याज भी शामिल होता है।

④ जनसंख्या में वृद्धि (Population growth) – जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है फलस्वरूप सरकार को भोजन, वस्त्र आवास, रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य पर भारी मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है।

⑤ आर्थिक क्षेत्र में सरकार की सक्रीयता – वर्तमान समय में हर देश आर्थिक विकास करना चाहता। यही कारण है की सरकार को आर्थिक नियोजन में भारी उद्योगों का विकास तथा निजी क्षेत्रों का विकास करना चाहती है। अतः सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है।

6) आर्थिक सहायता (Economic assistance) — आधुनिक समय में विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता जा रहा है। प्रायः विकसित देश अर्द्धविकसित या पिछड़े देशों को आर्थिक सहायता और अनुदान तो देते ही हैं साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों की सहायता करना कर्तव्य बन गया है और सार्वजनिक व्यय बढ़ रहे हैं।

7) आर्थिक उतार चढ़ाव — अर्थव्यवस्था में तेजी तथा मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होती रहती है। फलस्वरूप सरकार को कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देना और समय समय पर वेतन में वृद्धि करना पड़ता है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ रही है।

8) अंतरराष्ट्रीय संबंध (International relation) — वर्तमान समय में प्रत्येक देश आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से देश में सौहार्दपूर्ण सम्बंध बनाने के लिए प्रयास करता है। अतः अन्य देशों में दूतावास के माध्यम से इस देश से नजदीकी सम्बन्ध बनाये रखता है।

9) तकनीकि परिवर्तन — वैज्ञानिक अविष्कारों के साथ साथ तेजी गति से तकनीकि परिवर्तन हो रही है। और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि

10) शहरी या नगरीकरण (urbanization) :- औद्योगिक विकास के साथ साथ शहरीकरण की प्रवृति भी लोगों में बढ़ रही है अर्थात सरकार को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध पड़ता है। जैसे पानी, बिजली, रौशनी, चिकित्सा, आदि पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है।

इस प्रकार ऊपर दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है की हाल के वर्षों में सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ रही है इसलिए प्रश्न उठता है की सार्वजनिक व्यय की क्या सीमा होनी चाहिए। अतः व्यय की सीमा निर्धारित करना आसान नहीं है फिर भी सार्वजनिक व्यय की उस ~~[illegible]~~ दिशा को उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक की व्यय से उत्पन्न होने वाले असंतोष संतोष के बराबर न हो जाए।